रेप-अपराधी को बचाने का प्रयास किया डा. संगीता अग्रवाल ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीके अस्पताल के डॉक्टरों के लिए कानून को ठेंगा दिखाना कोई नई बात नहीं है। निजी स्वार्थ और कामचोरी के लिए गंभीर मामले में ये डॉक्टर सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखने से जरा भी नहीं चूकते। ताजा मामले में अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही बलात्कार का शिकार एक किशोरी का गर्भपात तक कर डाला। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए डॉक्टर ने किशोरी के परिजनों पर दबाव बना कर अस्पताल की फाइल पर लिखवा लिया कि वे कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। जबकि नाबालिग से बलात्कार के मामले में पुलिस को सूचित कर कार्रवाई करना बेहद जरूरी होता है।

नियम के मुताबिक बलात्कार अथवा फौजदारी के मामले में जब कोई पीड़ित अस्पताल में पहुंचता है तो डाक्टरों द्वारा सबसे पहले एमएलसी काट कर पुलिस को सूचना देनी बहुत जरूरी होती है। जिसके बाद महिला पुलिस और कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में पीड़ित के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाती है। बलात्कार के मामले में मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन बीके अस्पताल की गायनॉलॉजिस्ट डा. संगीता अग्रवाल ने सभी नियम और कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा डाली।

गत 16 नवंबर को बलात्कार पीड़िता एक किशोरी के परिजन गर्भपात करवाने के लिए उसे बीके अस्पताल में ले आए। जहां ड्यूटी पर मौजूद गायनॉलॉजिस्ट संगीता अग्रवाल ने न जाने किस लालच में पड़ कर पुलिस को सूचना देने की जरूरत महसूस नहीं की। बाद में वह कहीं वह फंस न जाए इस डर से किशोरी के परिजनों से अस्पताल की फाइल पर लिखवा लिया कि वे कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते है। जिसके बाद डाक्टर ने आनन फानन में किशोरी का गर्भपात कर उसे जच्चा बच्चा वार्ड में दाखिल कर दिया। जबकि इस तरह के मामले में पीड़िता को सुकुन सेन्टर में दाखिल किया जाता है।

डॉ. संगीता अग्रवाल की इस घिनौनी हरकत का खुलासा उस समय हुआ, जब अगले दिन यानी 17 नवंबर को एक अन्य गायनॉलॉजिस्ट वार्ड में राउंड पर आई। पूछताछ करने पर किशोरी ने गर्भपात के बारे में बताया तो डाक्टर हैरान रह गई। डाक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत किशोरी की एमएलसी कटवाई और पुलिस को सूचना दे दी। जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और किशोरी के बयान लेने के बाद मेडिकल टेस्ट करवाया गया। 19 नवंबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस ने यह मामला तो दर्ज कर लिया। लेकिन गर्भपात करने वाली डा. संगीता अग्रवाल की करतूत के कारण अब पुलिस के लिए आरोपी को सजा दिलवाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि बलात्कार के मामले में पुलिस को आरोपी को दोषी साबित करने के लिए विभिन्न तरह के करीब एक दर्जनभर से 'ज्यादा सैम्पल लेने होते है। इनमें भ्रूण के डीएनए का सैम्पल भी विशेष रूप से लिया जाता है। लेकिन मेडिकल से पहले ही किशोरी का गर्भपात किया जा चुका था। ऐसे में डीएनए का सैम्पल लेना पुलिस के लिए किसी तरह से संभव नहीं है।

ऐसा नहीं है कि अस्पताल के अस्थाई पीएमओ डॉ. राजीव बातीश और सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा को इस बारे में पता नहीं है। मामला उजागर होने के बावजूद इन दोनों ने महिला डाक्टर के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर उससे पूछताछ करने तक की जरूरत महसूस नहीं की।

निर्भया कांड के बाद पारित पॉक्सो एक्ट के मुताबिक नाबालिग से हुए यौन-अपराध की तुरन्त पुलिस में सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी भी सहअभियुक्त हो जाता है। इस हिसाब से डा. गुलशन अरोड़ा और डा. संगीता को भी पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था।

बीके अस्पताल में आम चर्चा है कि डॉ. संगीता अग्रवाल यहां आने वाली गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों के साथ बदतमीजी से बात तो करती ही है कई बार दुर्व्यवहार करने से भी नहीं चूकती। अनेकों शिकायते होने के बावजूद यह डाक्टर यहीं पर कई सालों से जमी हुई हैं। वह इस तरह की हरकत सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा की हिस्सापत्ती और स्थानीय नेताओं का संरक्षण मिलने की वजह से करती है।

साढ़े तीन साल बाद भी रेप जांच सेंटर में नही जुटाई सुविधाएं

फरीदाबाद। रा'य सरकार ने गुड़गांव व फरीदाबाद के सिविल अस्पतालों में पॉयलेट प्रोजेक्ट रूप में बलात्कार पीड़िताओं के लिए करीब साढ़े तीन साल पहले एक विशेष सेंटर शुरू किया था। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी शहर के बादशाह खान अस्पताल में चल रहे इस रेप जांच सेंटर (सूकुन) में मात्र दो पुलिस कर्मियों और पीड़िताओं को दाखिल करने के लिए तीन बिस्तरों के अलावा कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सरकार के द्वारा शुरू किए गए पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत इस सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टर, वकील, काउंसलर, नर्स व पुलिस कर्मचारी तैनात रहने चाहिए। जो पीडिता को न्याय दिलाने में मदद करते। लेकिन अब तक इस कक्ष में मात्र पुलिस के अलावा अन्य किसी को भी तैनात ही नही किया गया हैं। जिसके कारण बीके अस्पताल में आने वाली बलात्कार पीड़िताओं को आज भी इधर से उधर भटकना पड़ता हैं।

26 दिसंबर 2012 में चलती बस में हुए निर्भया गैंग रेप के बाद शुरू हुए भारी विरोध और जन आंदोलन को देख कर उन पीड़ितों के हौंसले भी बढ़ गए जो इससे पहले शिकायत करने से डरती थी। घटना के बाद बलात्कार पीड़िताओं के मामले ज्यादा सामने आने लगे। जिसके कारण राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि सिविल अस्पतालों में बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक अलग से सेंटर बनाया जाए। ताकि बलात्कार पीड़िताओं को मेडिकल करवाने के लिए इधर से उधर चक्कर न काटने पड़े। उन्हें व उनके परिजनों को लोगों के आगे शर्मसार न होना पड़े। जिसको देखते हुए बीके अस्पताल में दिखावे के लिए जांच सेंटर बना दिया गया था। लेकिन सेंटर के लिए घोषित पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति जिला प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण अब तक नही की गई। जिसके कारण यहां आने वाली बलात्कार पीड़िताओं और उनके परिजनों को लोगों के आगे शर्मसार होने को मजबूर होना पड़ता हैं। मेडिकल के दौरान उन्हें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। इस मेडिकल जांच सेंटर में बलात्कार पीडिताओं के साथ घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं की मदद करने की योजना भी बनाई गई थी। सेंटर को पांच बिस्तरों का बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें 'राउंड द क्लाक' विशेषज्ञ व पुलिस और वकील मौजूद रखने का निर्णय लिया गया था। जांच के लिए एक विशेष प्रकार की कीट उपलब्ध कराई जानी थी। इसके माध्यम से पीडिता के 20-22 प्रकार के नमूने लिए जाते। इसे मौके पर ही सील कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपा जाता। लेकिन बीके में आने वाली बलात्कार पीड़िताओं के लिए मात्र तीन बिस्तरों का कक्ष और दो पुलिस कर्मियों की रोजाना डयूटी के अलावा इस सेंटर में कुछ भी मौजूद नही है। सेंटर में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक स्टाफ नर्स, एक काउंसलर, एक वकील व एक पुलिस कर्मी और दो सफाई कर्मचारियों 24 घंटे तैनात रखने का आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है।

भ्रष्ट और नशेड़ी कर्मचारियों की लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहे है सीएमओ

फ़रीदाबाद। (म.मो.) बीके अस्पताल में सरेआम शराब पीने की घटना कोई नई नहीं है। अस्पताल के पुराने भवन का परिसर तो पहले से ही मैखाने के नाम से मशहूर है। परिसर में सिविल सर्जन कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर नगर निगम के कर्मचारियों और अन्य असामाजिक तत्वों को दिन के समय ही जाम टकराते देखा जा सकता है।

गत 18 नवंबर की देर शाम को बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा ने दो अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों और एक सेवानिवृत अकाउंटेंट को पीएमओ कार्यालय के ठीक सामने बने फार्मासिस्ट के कक्ष में शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। यह 'सराहनीय' कार्य त्रिखा ने एक व्यक्ति की शिकायत पर किया था। वह व्यक्ति इत्तेफाक से जांच रिपोर्ट लेने के लिए प्रयोगशाला में गया था। उसी दौरान प्रयोगशाला के पास बने कमरे में उसने इन तीनों को जाम टकराते देख लिया।

शराबियों को पकड़ने का श्रेय लेने के लिए तो सीमा त्रिखा तुरंत अस्पताल पहुंच गई। लेकिन त्रिखा ने आज तक अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत महसूस नहीं की। ऐसा नहीं है कि सीमा त्रिखा को इस बारे में पता नहीं है। अस्पताल में दवाइयों और अन्य तरह की कमियों की शिकायतें उन्हें लोगों से मिलती ही रहती हैं।

पिछले दिनों सीमा त्रिखा एक निजी प्रयोगशाला के निमंत्रण पर फल बांटने के लिए अस्पताल में आई थीं। उस समय उनसे स्टॉफ नर्सो की कमी की शिकायत यहां नाम मात्र को बची नर्सो ने की थी। लेकिन सीमा ने इस शिकायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया।

दूसरी तरफ यदि इन शराबियों को पकड़ भी लिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अस्थाई पीएमओ ने तो इन तीनों के खिलाफ लिखित शिकायत देने से ही इनकार कर दिया था। इस पर पुलिस इन्हें ले जाने को तैयार नहीं हुई तो दबाव बनाया गया। मजबूरी में पुलिस ने धारा 160 तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की। धारा 160 तब लगाई जाती है, जब कोई व्यक्ति शराब पीने के बाद सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करें। अस्पताल प्रशासन की करतूत से यह साबित हो गया कि इन कर्मचारियों ने अस्पताल में बैठ कर शराब पी ही नहीं है।

यह मामला सामने आने के बाद अस्थाई पीएमओ डॉ. राजीव बातीश तो मौके पर पहुंच गए। लेकिन सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा नदारद रहे है। इसका कारण यह है कि डॉ. गुलशन अरोड़ा ने अस्पताल परिसर में मकान सिर्फ दिखावे के लिए लिया हुआ है। लेकिन वास्तव में वे हर रोज शाम को गुड़गांव स्थित अपने घर लौट जाते है। जबकि अस्पताल परिसर में मकान सिर्फ इस शर्त पर मिलता है कि वे रात को यहीं पर रुकेंगे।

सूत्र बताते हैं कि वे मकान में रुकते ही नहीं है। पिछले दिनों इस मकान में जब चोरी हुई थी तो उस समय भी अरोड़ा यहां मौजूद नहीं थे। हां घटना के बाद उन्होंने इतना जरूर किया है कि अस्पताल की तीसरी मंजिल में रात को जो सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहता है, उसकी ड्यूटी अपने सरकारी मकान में लगा दी। यदि रात को यह सुरक्षा कर्मचारी तीसरी मंजिल में मौजूद रहता तो वह इन तीनों शराबियों को शराब पीने से रोक सकता था। मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा किस तरह से अस्पताल का दुरूपयोग कर रहे हैं।

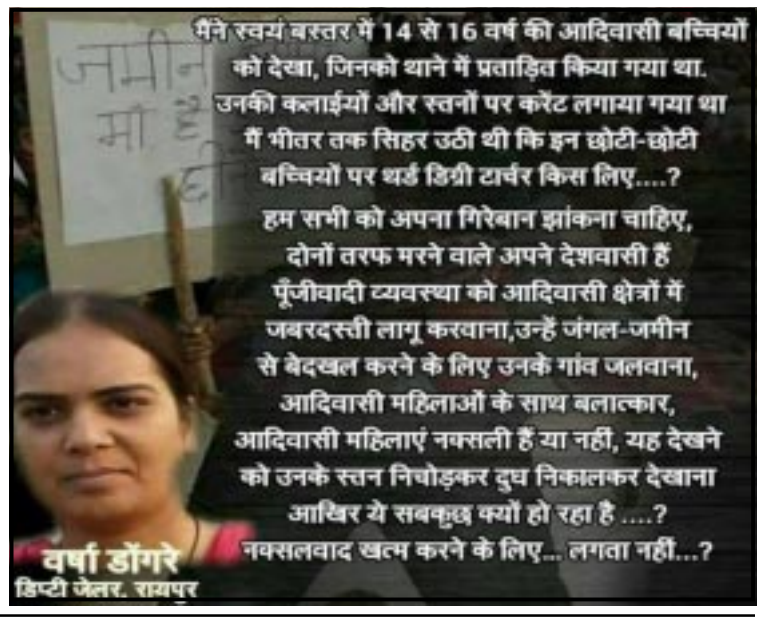

आदरणीय मोदी जी ! आप की सरकार ने तो मैकाले को भी पीछे छोड़ दिया

सम्पादक के नाम

आदरणीय मोदी जी! आप जिस तरह झूम झूम कर मंत्रमुग्ध कर देने वाला भाषण हिन्दी में देते हैं क्या उसी तरह का प्रभावशाली भाषण अंग्रेजी में भी दे सकते हैं ? आप जिस तरह अपने को हिन्दी में अभिव्यक्त कर लेते हैं क्या उसी तरह अंग्रेजी में भी कर सकते हैं ? नहीं न ? विश्वास कीजिए हम सबके साथ ऐसा ही होता है.

'इंडियन एक्सप्रेस' के गत 30 अक्टूबर 2017 के अंक में छपी खबर के अनुसार आप की सरकार ने दिल्ली कारपोरेशन के अंतर्गत आने वाले सभी 1700 से अधिक स्कूलों को आगामी मार्च से अंग्रेजी माध्यम में बदल देने का फैसला लिया है. इसी तरह का फैसला गत जून के अंतिम हफ्ते में उत्तराखंड की सरकार ने अपने यहां के 18000 से भी अधिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बनाने की घोषणा करके लिया था.

महोदय, आप की सरकार का यह निर्णय हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, यह निर्णय इस देश के अस्सी प्रतिशत प्रतिभाशाली बच्चों के मौलिक अधिकारों का भी हनन है और उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल होने से रोकना है.

मान्यवर, आप जब प्रधान मंत्री बने थे तो हम बहुत खुश थे. हमें लगा कि हमारे बीच का एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, संघर्ष झेला है वह हमारा नेतृत्व करेगा और हमारे हित में जरूर फैसले लेगा. किन्तु, आप की सरकार ने तो मैकाले को भी पीछे छोड़ दिया. मैकाले भी इस देश में बुनियादी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने की हिम्मत नहीं जुटा सका था. आप भली भांति जानते हैं कि इस देश के मुट्ठीभर लोगों ने सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए अंग्रेजी को एक हथियार की तरह अपनाया हुआ है. जबतक हमारी शिक्षा हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से नहीं होंगी तबतक गांवों की दबी हुई प्रतिभाओं को मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिलेगा. आजादी के बाद इस विषय को लेकर राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग आदि अनेक आयोग बने और उनके सुझाव भी आए. सबने एक स्वर से यही संस्तुति की कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा सिर्फ मातृभाषाओं में ही दी जानी चाहिए. दुनिया के सभी विकसित देशों में वहां की मातृभाषाओं में ही शिक्षा दी जाती है. मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि अपनी मातृभाषा में बच्चे खेल खेल में ही सीखते हैं और बड़ी तेजी से सीखते हैं. उनकी कल्पनाशीलता का खुलकर विकास मातृभाषाओं में ही हो सकता है. गाँधी जी चाहते थे कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ मातृभाषा के माध्यम से हो. 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा है, अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही हमारे लड़के और लड़कियों की विदेशी माध्यम के जरिये शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूं या उन्हें बरखास्त कर दूं. मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा. वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे चली आवेंगी. 'हिन्द स्वराज' में उन्होंने लिखा कि, अंग्रेजी शिक्षण से दंभ द्वेष अत्याचार आदि बढ़े हैं. अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने जनता को ठगने और परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी. भारत को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं.

आप स्वयं जिस 'विश्वभारती', शान्तिनिकेतन के चांसलर हैं उसके संस्थापक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के माध्यम विषय पर कहा हैं, हमारा मन तेरह ङ्क्चौदह वर्ष की आयु से ही ज्ञान का प्रकाश तथा भाव का रस प्राप्त करने के लिए खुलने लगता है. उसी समय यदि उसके ऊपर किसी पराई भाषा के व्याकरण तथा शब्दकोश रटने के रूप में पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी जाय तो बतलाइए कि वह सुदृढ़ और शक्तिशाली किस प्रकार हो सकता है? उल्लेखनीय है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा इंग्लैंड में अंग्रेजी माध्यम से हुई थी और उनके जीवन के प्रारंभिक आठ वर्ष यूरोप में ही व्यतीत हुए थे. आप को पता ही होगा, 'विश्वभारती' की माध्यम-भाषा उन्होंने बांग्ला को ही चुना.

महोदय, आप ने पिछले दिनों एक लाख करोड़ की लागत वाली जापान की तकनीक और कर्ज के बलपर जिस बुलेट ट्रेन की नींव रखी है उस जापान की कुल आबादी सिर्फ 12 करोड़ है. वह छोटे छोटे द्वीपों का समूह है. वहां का तीन चौथाई से अधिक भाग पहाड़ है और सिर्फ 13 प्रतिशत हिस्से में ही खेती हो सकती है. फिर भी वहां सिर्फ भौतिकी में 13 नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक हैं. ऐसा इसलिए है कि वहां 99 प्रतिशत जनता अपनी भाषा 'जापानी' में ही शिक्षा ग्रहण करती है. इसी तरह कुछ दिन पहले आप ने जिस इजराइल की यात्रा की थी और उसके विकास पर लट्टू थे उस इजराइल की कुल आबादी मात्र 83 ह्यलाख है और वहां 11 नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं क्योंकि वहां भी उनकी अपनी भाषा 'हिब्रू' में शिक्षा दी जाती है. चीन के राष्ट्रपति का स्वागत भी आप कर चुके हैं. चीन उसी तरह का बहुभाषी विशाल देश है जिस तरह का भारत. किन्तु उसने भी अपनी एक भाषा चीनी (मंदारिन) को प्रतिष्ठित किया और उसे वहां पढ़ाई का माध्यम बनाया. चीनी बहुत कठिन भाषा है. चीनी लिपि दुनिया की संभवतः सबसे कठिन लिपियों में से एक है. वह चित्र-लिपि से विकसित हुई है. आज चीन जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि उसने अपने देश में शिक्षा का माध्यम अपनी चीनी भाषा को बनाया. इसी तरह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि दुनिया के सभी विकसित देशों में वहां की अपनी भाषाओं क्रमशः अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि में ही शिक्षा दी जाती है. इसीलिए वहां मौलिक चिन्तन संभव हो पाता है. मौलिक चिन्तन सिर्फ अपनी भाषा में ही हो सकता है. व्यक्ति चाहे जितनी भी भाषाएं सीख ले किन्तु सोचता अपनी भाषा में ही है. हमारे बच्चे दूसरे की भाषा में पढ़ते हैं फिर उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके सोचते हैं और लिखने के लिए फिर उन्हें दूसरे की भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है. इस तरह हमारे बच्चों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरे की भाषा सीखने में चला जाता है. अंग्रेजी माध्यम अपनाने के बाद से हम सिर्फ नकलची पैदा कर रहे हैं. अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षा सिर्फ नकलची ही पैदा कर सकती है.

आप तो अपनी विरासत समझते हैं! याद कीजिए, जब अंग्रेज नहीं आए थे और हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे तब हमने दुनिया को बुद्ध और महावीर दिए, वेद और उपनिषद दिए, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र दिए, चरक जैसे शरीर विज्ञानी और शुश्रुत जैसे शल्य-चिकित्सक दिए, पाणिनि जैसा वैयाकरण और आर्य भट्ट जैसे खगोलविज्ञानी दिए, पतंजलि जैसा योगाचार्य और कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री दिए. हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे. इस देश को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था जिसके आकर्षण में ही दुनिया भर के लुटेरे यहां आते रहे. प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश की संस्कृति से मुकाबला करने के लिए अपने यहां के सिर्फ तीन नाम ले लेना ही काफी है- तानसेन, तुलसीदास और ताजमहल.

मोदी जी, इस समय हमारे देश में 8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते. सबसे पहले उन्हें स्कूल भेजने की व्यवस्था कीजिए, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कीजिए, सरकारी विद्यालयों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराइए. शिक्षा का क्षेत्र आज भारी मुनाफे का क्षेत्र हो गया है. सबसे ज्यादा निवेश यहीं हो रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है. वह मालिकों की चापलूसी में लगा रहता है, शिक्षा क्या देगा ? इसपर अंकुश लगाइए और शिक्षा को पूरी तरह न हो सके तो अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण में ले आइए. यहीं भावी नागरिक तैयार होते हैं. इससे पल्ला झाड़ना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

मोदी जी, अंग्रेजी ही ज्ञान की भाषा है- यह बहुत बड़ा झूठ है. यह गलत अफवाह फैलाया जाता है कि उच्च शिक्षा (ज्ञान-

शेष पेज सात पर